जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 327 प्रभात चूरू, शुक्रवार 27 मार्च, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

दो दिन बचे हैं, ''डैड लाइन'' पूरी होने में

कांग्रेस बदहवास सी दिख रही है, अकबर रोड स्थित मुख्यालय को बचाने के प्रयास में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मार्च। पिछले 48 वर्षों से कांग्रेस का मुख्यालय रहे 24, अकबर रोड को खाली करने के लिए अंतिम नोटिस दिए जाने के बाद, पार्टी अपने इस परिसर को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने बैक-चैनल कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए सरकार के उन लोगों से मीटिंग करने की कोशिश की है, जो मदद कर सकते हैं, लेकिन अब तक सभी प्रयास विफल रहे हैं और सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है।

यह स्पष्ट रूप से शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर हो रहा है। इसके साथ ही, युवा कांग्रेस कार्यालय 5 रायसीना रोड और जवाहर भवन को भी खाली करने के लिए कहा गया है।

यूपीए सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें राजनीतिक दलों से, लुटियंस दिल्ली के बाहर स्थानांतरित करने को कहा गया था, क्योंकि यहां ट्रैफिक जाम और अन्य समस्याएं हो रही थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने का आदेश दिया था और यूपीए सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को जमीन आवंटित की थी।

पिछले नवंबर में कांग्रेस ने अपने नए पार्टी कार्यालय ''इंदिरा भवन'' का उद्घाटन किया, लेकिन पार्टी 24 अकबर रोड को किसी कांग्रेस सांसद के नाम पर आवंटित करवाने में पूर्णतया विफल रहीं।

यह भवन कांग्रेस पार्टी के नाम पर ही आवंटित रहा। इन मुद्दों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कांग्रेस ने ''बैक चैनल डिप्लोमैसी'' के मार्फत भाजपा नेताओं से बातचीत भी की, पर, सब जगह उनके प्रयास निष्फल हुए।
- यह समस्या खड़ी ही नहीं होती, अगर, कांग्रेस ने 24, अकबर रोड स्थित बंगले को अपने किसी सांसद के नाम ''अलॉट'' करा लिया होता, पर, बंगला औपचारिक तौर पर, कांग्रेस पार्टी को आवंटित दिखाया जाता रहा।
- एआईसीसी में प्रशासनिक व्यवस्था देखने वाले लोगों की यह जिम्मेवारी थी, पर, लगता है पूरी व्यवस्था ही खत्म हो गई है। अतः, अब बदहवास सी स्थिति दिख रही है, पार्टी में, क्योंकि कोर्ट की शरण में जाने के विकल्प में कुछ दम नहीं लगता, क्योंकि, भूमि आवंटित करके, पार्टी को मुख्यालय के निर्माण के लिए पर्याप्त समय पहले ही दिया जा चुका है।
- जैसा कि विदित ही है, यूपीए सरकार के शासनकाल में, सुप्रीम कोर्ट ने रोजमर्रा ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से निपटने के लिए फैसला सुनाया था कि लुटियंस एरिया से सभी राजनीतिक पार्टियों को बाहर शिफ्ट करवा देना चाहिए तथा सरकार ने राजनीतिक पार्टियों को भूमि भी आवंटित कर दी थी, नया मुख्यालय बनाने के लिए।

ईरान वॉर के कारण महंगी हुई स्वास्थ्य सेवाएं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मार्च। सभी क्षेत्रों की तरह भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र भी ईरान में चल रहे युद्ध के अप्रत्यक्ष प्रभावों को महसूस करने लगा है। हालांकि अभी तक नियमित चिकित्सा सेवाओं में कोई बडा व्यवधान नहीं आया है, लेकिन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि लंबे समय तक संघर्ष जारी रहने से सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि होर्मुज़ स्ट्रेट जैसे शिपिंग मार्ग लंबे समय तक प्रभावित रहे, तो इसका असर अंततः मरीजों की जेब पर पड़ेगा।

भारत के मेडिकल डिवाइस और फार्मा सेक्टर बड़ी मात्रा में कच्चा माल, सक्रिय औषधीय तत्व (एपीएल) और विशेष घटक (कम्पोनेन्ट्स) आयात करते हैं, जिनमें प्लास्टिक और इन्टरमीडिएट केमिकल शामिल हैं। महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में हो रही देरी, बढ़ी हुई ढुलाई लागत और ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण स्वास्थ्य कंपनियों की लागत बढ़ रही है। सिरिंज, ग्लव्स, कैथेटर और अन्य कन्ज्यूमेबल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भारत के बड़े पैमाने पर चिकित्सकीय उपकरण, दवाओं के घटक आदि आयात होते हैं। इस समय ईरान वॉर के कारण माल आना मुश्किल हो गया है।

भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल, जिन्हें ईरान अपना मित्र मानता है

इन देशों की सूची में भारत के साथ चीन, रूस, ईराक, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मार्च। एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में, ईरान ने कहा है कि मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होर्मुज़ स्ट्रेट (जलडमरूमध्य) भारत के लिए खुला रहेगा। यह जलमार्ग, जो फारस की खाड़ी का संकरा मुहाना है और जिसके माध्यम से सामान्यतः दुनिया के पाँचवें हिस्से का तेल भेजा जाता है, पिछले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किए जाने के बाद से ईरान के नियंत्रण में है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ईरान के सरकारी टीवी से बातचीत में स्पष्ट किया कि, पश्चिमी मीडिया के दावों के विपरीत, यह स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अराघची ने कहा, ''कई जहाज मालिकों, या उन देशों ने, जो इन जहाजों के मालिक हैं, हमसे संपर्क किया है और स्ट्रेट से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इनमें से कुछ देशों को मित्रता के लिए तथा कुछ को अन्य कारणों से हमने सुरक्षित मार्ग देने का विचार किया है। हमारी सेनाओं ने उन्हें रास्ता दिया है। उन्होंने आगे कहा, ''आपने खबरों में देखा होगा: चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत। कुछ रात पहले उनके दो जहाज यहां से गुज़रे, और कुछ अन्य देश, यहाँ तक कि मुझे लगता है बांग्लादेश भी। ये वे देश हैं, जिन्होंने हमसे बात की और हमारे साथ तालमेल किया, और यह भविष्य में भी, युद्ध के बाद भी, जारी रहेगा।

- ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से इन देशों के जहाजों के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
- ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ईरान के सरकारी टीवी पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की यह खबर झूठी है, हमने होर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह बंद किया है। जिन देशों को हम मित्र मानते हैं, उन्हें हमने सुरक्षित रास्ता दिया है।
- अराघची ने कहा, आपने खबरों में देखा होगा, दो दिन पहले भारत के दो जहाज होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरे थे।

होर्मुज़ स्ट्रेट के पास 1900 जहाज फंसे हैं

लंदन/तेहरान, 26 मार्च। पश्चिम एशिया में पिछले 27 दिनों से जारी युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में, मुख्य रूप से फारस की खाड़ी में, लगभग 1,900 व्यापारिक जहाज फंसे हुए हैं। युद्ध शुरु होने के बाद होर्मुज में समुद्री यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कतर से गैस आयात घटाना भारत के लिए वरदान बना

भारत ने 2014 के बाद से कतर से गैस आयात घटाना शुरु कर दिया था, इससे पूर्व भारत कुल गैस उपभोग का 86 प्रतिशत कतर से मंगाता था

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मार्च। 19 मार्च को क़तर के रास लफ़ान हाइड्रोकार्बन कॉम्प्लेक्स पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी, क्योंकि क़तर दुनिया की लिक्विफाइड नैचुरल गैस (एलएनजी) के लगभग पाँचवें हिस्से की आपूर्ति करता है। यह चिंता भारत में विशेष रूप से गंभीर थी, क्योंकि हमारी जरुरत की एलएनजी का 40 प्रतिशत क़तर से आता है।

इस कॉम्प्लेक्स के अनिश्चितकाल के लिए बंद होने और होर्मुज़ स्ट्रेट को जहाजों के लिए बंद करने की स्थिति में, क़तर की गैस पर भारत की निर्भरता घातक लग सकती है। ऐसा है, लेकिन केवल बहुत कम समय के लिए। ऐतिहासिक आयात आंकड़े बताते हैं कि एक दशक पहले भारत की निर्भरता इससे कहीं अधिक थी; लेकिन 2014 के बाद भारत सरकार ने क़तर की गैस पर निर्भरता कम करने के लिए एक सुविचारित रणनीति शुरू की। यह इस बात का उदाहरण है कि दूरदृष्टि को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ज्ञातव्य है कि 19 मार्च को ईरान के हमले में कतर का सबसे बड़ा, रास लाफान हाइड्रोकार्बन्स कॉम्पलैक्स ध्वस्त हो गया और यह अगले कुछ माह तक बंद रहेगा। अगर भारत सिर्फ कतर पर ही निर्भर रहता तो भारी दिक्कत में पड़ सकता था।
- सन् 2014 में मोदी सरकार ने कतर पर गैस निर्भरता घटानी शुरु की, जो 86 प्रतिशत से घट कर 39 प्रतिशत रह गई है।
- इस समय भारत कतर के अलावा नाइजीरिया, इक्वटोरियल गिनी, ऑस्ट्रेलिया और ओमान से गैस ले रहा है।

राजस्थान का कॉमर्शियल गैस आवंटन 10 प्रतिशत बढ़ा

जयपुर, 26 मार्च। प्रदेश में आवश्यक ईंधन आपूर्ति को लेकर बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केन्द्र सरकार ने राजस्थान को अतिरिक्त कमर्शियल गैस का आवंटन 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केन्द्र से अतिरिक्त आवंटन की मांग की थी, जिस पर सकारात्मक निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गैस, पेट्रोल और डीज़ल की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रधानमंत्री का आभार जताया।

'ईरान ने हमें गिफ्ट में 10 ऑइल टैंकर दिए, दूसरे देशों के लगे थे झंडे'

वाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दावे किए कई

वॉशिंगटन, 26 मार्च। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनको ईरान से गिफ्ट में तेल के टैंकर मिले हैं। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत को लेकर अपनी गंभीरता दिखाने के लिए तोहफे के तौर पर होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका के 10 तेल टैंकरों को गुजरने की अनुमति दी। हालांकि इन जहाजों पर झंडे दूसरे देशों के थे। खासतौर से इनमें पाकिस्तान के झंडे वाले जहाज शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे बातचीत के बीच सद्भावना का संकेत बताया।

वाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक के दौरान बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि यह घटनाक्रम वाशिंगटन और तेहरान के बीच सीक्रेट लेकिन सक्रिय जुडाव को दिखाता है। ट्रंप ने कहा, उन्होंने कहा कि यह दिखाने के लिए कि हम भरोसेमंद हैं, हम आपको तेल के आठ बड़े जहाज ले जाने देंगे। इसके बाद दो और अमेरिकी जहाजों को रास्ता दिया गया।

डॉनल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने न्यूज देखी तो उसमें बताया गया कि कुछ अजीब हो रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य के ठीक बीच से आठ नावें गुजर रही हैं। न्यूज में दिखा रहे थे कि तेल से भरे आठ बड़े टैंकर सीधे वहां से गुजर रहे थे। मुझे लगता है कि वे सही कह रहे थे। ईरान ने हमें भरोसा दिलाने के लिए उनको वहां से निकाला और ये जहाज पाकिस्तानी झंडे वाले थे ट्रंप ने आगे कहा कि बाद में टैंकरों की संख्या बढ़ गई। यह ईरान की ओर से हमें भरोसे में लेने के लिए एक अगली कार्रवाई थी। उन्होंने अपनी किसी बात के लिए माफी मांगी और कहा कि हम दो और नावें भेजेंगे। इस तरह कुल मिलाकर 10 नावों का तोहफा हमें मिला। साफ है किटैंकरों की आवाजाही पर्देके पीछे चल रही व्यापक बातचीत से जुड़ी थी।

- ट्रंप ने कहा, ईरान ने कहा कि यह दिखाने के लिए कि हम भरोसेमंद हैं, हम आपको तेल के आठ बड़े जहाज ले जाने देंगे। इसके बाद दो और अमेरिकी जहाजों को रास्ता दिया गया।
- डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को यह भी कहा कि यह पूरी तरह से फेक है कि अमेरिका डील चाहता है। मैं डील नहीं करना चाहता हूं। असल में वे डील करने की भीख मांग रहे हैं।
- डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी पब्लिक में कह रहे हैं कि हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं। असल में वे खास मायने में बहुत होशियार हैं और बातचीत करने में माहिर हैं। वे डील पक्की करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं।

इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड के नौसेना कमांडर अलीरेज़ा तंगसीरी, इज़रायली बमबारी में मारे गए

तंगसीरी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से आवागमन बंद करने के प्लान के रचयिता थे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मार्च। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के नौसैनिक कमांडर अलीरेज़ा तंगसीरी की बंदर अब्बास के तटीय क्षेत्र में अमेरिका-इज़रायल के हमले में मौत हो गई है। इज़रायली मीडिया ने एक इज़रायली अधिकारी के हवाले से यह खबर दी। टाइम्स ऑफ इज़रायल की रिपोर्ट के अनुसार, तंगसीरी होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कराने के लिए जिम्मेदार थे।

इज़रायली मीडिया का दावा है कि इससे अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट बिना किसी अतिरिक्त नाकाबंदी के खुल गया है।

इस हमले पर अभी तक ईरान या इज़रायली सेना की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। यदि इसकी पुष्टि होती है, तो यह अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुके युद्ध में एक और बड़ा नुकसान होगा।

तंगसीरी उन कुछ बड़े नामों में शामिल थे, जो अब तक अमेरिका-इज़रायल के हत्या प्रयासों से बचते रहे थे। सन् 2018 से इस पद पर रहे एक अनुभवी कमांडर के रूप में उन्होंने होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

फारस की खाड़ी से खुले समुद्र की ओर जाने वाले इस रणनीतिक मार्ग होर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण रखते हुए, ईरान उन जहाजों को रोक रहा था, जिन्हें वह अमेरिका और इज़राइल के युद्ध प्रयासों से जुड़ा मानता है, जबकि कुछ अन्य जहाजों को सीमित रूप से गुजरने दे रहा था। सामान्य समय में, दुनिया भर में बेचे जाने वाले कुल तेल और प्राकृतिक गैस का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है।

तेहरान द्वारा इस मार्ग पर लगाए गए नियंत्रण के कारण इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से ऊर्जा की दैनिक शिपिंग में 95 प्रतिशत की गिरावट आई है। शिपिंग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हालांकि, अभी तक ईरान या इज़रायल ने इस बमबारी की खबर की पुष्टि नहीं की है।
- अगर, इस बमबारी में तंगसीरी की मृत्यु की पुष्टि हो गई तो तंगसीरी का नाम उन चुनिंदा नामों में अव्वल नम्बर पर होगा, अब तक जिन्हें अमेरिका-इज़रायल बमबारी नहीं मार पाई थी।
- तंगसीरी 2018 से अपने इस पद पर विराजमान थे, जिसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जहाजों के आवागमन को प्रतिबंधित किया था।

'देश के पास 60 दिन का तेल और गैस का पर्याप्त भंडार'

नई दिल्ली, 26 मार्च। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि देश के पास करीब 60 दिनों का पर्याप्त ईंधन भंडार है। पेट्रोल, डीजल या घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कोई कमी नहीं है। सरकार ने ईंधन की कमी की खबरों को अफवाह बताकर लोगों से भरोसा न करने को कहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रण में है। सभी खुदरा ईंधन आउटलेट्स पर पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। देश में कहीं भी पेट्रोल-डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे जान-बूझकर चलाए जा रहे एक शरारतपूर्ण और सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान से गुमराह न हों, जिसका उद्देश्य बेवजह घबराहट फैलाना है।

मंत्रालय ने कहा कि देशभर में 1 लाख से ज्यादा रिटेल ईंधन आउटलेट खुले हैं और बिना किसी रुकावट के ईंधन दे रहे हैं। किसी भी आउटलेट से सप्लाई को सीमित करने के लिए नहीं कहा गया है। सभी पेट्रोल पंप पर पर्याप्त स्टॉक है। वे सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। पेट्रोल या डीजल की कोई राशनिंग नहीं की जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन के मामले में दुनिया में चौथे और पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक भारत, घरेलू ईंधन की उपलब्धता को संरचनात्मक रूप से सुनिश्चित करता है। साथ ही 150 से ज्यादा देशों को परिष्कृत ईंधन की आपूर्ति करता है।

मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के 27वें दिन भी हमारे पास अभी करीब 60 दिन का वास्तविक ईंधन भंडार है, जिसमें कच्चे तेल का भंडार, उत्पाद भंडार और रणनीतिक भंडारण शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि दो माह की कच्चे तेल की खरीद पहले ही सुनिश्चित होने की वजह से अगले कुछ माह तक भारत के लिए समस्या नहीं है, इसलिए देश में भंडार के समाप्त या अपर्याप्त होने के किसी भी दावे को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए।

- सरकार ने ईंधन की कमी की खबरों को अफवाह बताकर लोगों से भरोसा न करने को कहा
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रण में है। सभी खुदरा ईंधन आउटलेट्स पर पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। देश में कहीं भी पेट्रोल-डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है।

बांग्लादेश पद्मा नदी बस हादसे में 26 लोगों की मौत

ढाका, 26 मार्च। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में एक बस को फेरी पर चढ़ाने के दौरान हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ कर 26 हो गई है। बुधवार की देर शाम राजबाड़ी जिले की दौलतदिया फेरी टर्मिनल पर यात्रियों से भरी एक बस फेरी पर चढ़ाते समय पद्मा नदी में गिर गई थी। बचाव अभियान के बाद बस को देर रात नदी से बाहर निकाला गया। घटना के बाद जिला प्रशासन ने पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जिसे तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, मृतकों के परिजनों को प्रारंभिक मुआवजे के तौर पर 25,000 टका देने की घोषणा की गई है।

बांग्लादेश की प्रमुख समाचार पत्र ढ ाका ट्रिब्यून और प्रथम आलो के अनुसार, बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के गोआलैंड उपजिला स्थित दौलतदिया फेरी टर्मिनल पर बुधवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जब यात्रियों से भरी एक बस पद्मा नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।